पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

(एस.सी. मित्तल से पहले)

वरयाम सिंह... प्रार्थी;

बनाम

पंजाब राज्य... प्रतिवादी।

1977 का क्रिमिनल मिस्क नंबर 3905-एम और 1977 का क्रिमिनल मिस्क नंबर 3915

8 सितंबर, 1977 को फैसला

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था?

न्यायमूर्ति एस.सी. मित्तल, इस मामले पुलिस द्वारा धारा 307/325/324/323/149 और 148, दंड संहिता, 1860 के तहत जिन छह अभियुक्तव्यक्तियों का चालान किया गया था, उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जीरा द्वारा सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में, वरयाम सिंह को कॉलम नंबर 2 में उल्लेख किया गया था, यह दर्शाता है कि पुलिस के अनुसार उन्होंने शिकायत की गई अपराध नहीं किया था। जब फिरोजपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई की गई, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, वरयाम सिंह को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश पारित किया । व्यथित महसूस करते हुए, वरयाम सिंह ने आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत यह याचिका दायर की है।

2. *सुरिंदर कुमार* बनाम *पंजाब राज्य*[1] मामले में, मैंने यह विचार व्यक्त किया कि सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सुनवाई योग्य मामले में कार्यवाही करते समय मजिस्ट्रेट केवल उन अभियुक्तव्यक्तियों को दोषी ठहरा सकता है जिनका पुलिस द्वारा चालान किया गया है। संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध नहीं किया जा सकता था।

3. क्या उपरोक्त रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की स्थिति में सत्र न्यायालय, उपरोक्त रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की स्थिति में होगा, यह प्रश्न मेरे द्वारा खुला छोड़ दिया गया था। इस मामले में यह सवाल सीधे तौर पर उठ खड़ा हुआ है। इस संबंध में संदर्भ *दया सिंह* बनाम *पंजाब राज्य*[2] के लिए किया जा सकता है, जिसका निर्णय न्यायमूर्ति आरएन मित्तल द्वारा किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने संहिता की धारा 193 और 319 के प्रावधानों की जांच करने के बाद कहा कि सत्र न्यायालय के पास धारा 319 के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 में उल्लेख किया गया है।

वरयाम सिंह के वकील ने बताया कि *पाटांचला चीन लिंगैया* बनाम *राज्य*[3] में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने विपरीत विचार व्यक्त किया। इस विनिर्णय का उल्लेख आर.एन.मित्तल, जे. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 से पहले नहीं किया गया था-

> "इस संहिता द्वारा या किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अन्यथा प्रावधान के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया हो।

5. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपर्युक्त उद्धृत निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश, मैं यथोचित सम्मान के साथ कह सकता हूं, धारा 193 के "इस संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अन्यथा को छोड़कर" प्रारंभिक शब्दों को प्रभावी नहीं किया। *दया सिंह के मामले* (सुप्रा) में, आरएन मित्तल, जे ने धारा 193 में होने वाले इन शब्दों को पूरी तरह से प्रभावी बनाया और माना कि अपवाद संहिता की धारा 319 द्वारा प्रदान किया गया था। संहिता की धारा 319 के उपबंधों की पूर्ण जांच करने के बाद आर. एन. मित्तल, जे. ने कहा -

> "संहिता की धारा 193 और 319 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि सत्र न्यायालय द्वारा किसी मामले का संज्ञान लेने के बाद, उसके पास धारा 319 के तहत आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को तलब करने की शक्ति है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई अपराध किया है, जिसके लिए उसके साथ आरोपी के साथ व्यवहार किया जा सकता है।

6. मैं आर.एन. मित्तल, जे. मित्तल, जे. की उपर्युक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। इसलिए, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

आर.एम.एस.

7. *याचिका खारिज।*

---

[1] (1977) 79 पीएलआर 454।

[2] 1977 का सी.आर.एम. नं. 559-एम.

[3] 1977 सी.आर.एल.जे. 415.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा